जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 8 मासिक नई दिल्ली अप्रैल 2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादकः देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्कः 60रुपये

खाद्य सुरक्षा की गारण्टी कानून में ही नहीं, बल्कि व्यवहारिकता जरूरी

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

कई बार घोषित और आश्वस्त करने के बाद खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में कानून का रूप देने के लिये संप्रग सरकार को उसे अंतिम रूप देना बाकि है। सरकार द्वारा धैर्य बनाये रखने और वास्तविक रूप से कानून में परिवर्तित करने के लिये खाद्यान्न संकट प्रतिक्षा तो करेगा नहीं। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है देश बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। कृषि क्षेत्र में विकास दर अत्यंत न्यूनतम 1.5 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है वहीं गरीबी और भूखमरी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा हैं। तेंदुलकर कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी का 38 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने का बाध्य है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी का 77 प्रतिशत भाग मात्र 20 रुपये प्रतिदिन की आय पर गुजर बसर करने को बाध्य है। एक सामान्य आकलन के अनुसार 25 करोड़ भारतीय भूखे सो जाते हैं। पिछले पाँच दशकों में गरीबी और भूखमरी कई गुणा बढ़ी है और वर्तमान में इसने एक धधकते हुये ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। विश्व के तमाम 88 देशों के आधार पर तैयार भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। ऐसी परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा की समस्या भारत सरकार के लिये एक ज्वलंत समस्या बन गई है जिसे और अधिक नहीं टाला जा सकता। क्योंकि खाद्य सुरक्षा की गारण्टी का आधार खाद्यान्न आयात के ऊपर आश्रित नहीं रखा जा सकता। कृषि उत्पादकता को बल प्रदान करने की आवश्यकता है। परन्तु भारत सरकार वर्तमान कृषि से कहीं कोई आशा की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है।

खाद्यान्न की सुरक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है, इसे वैकल्पिक रूप में नहीं लिया जा सकता। अगर यह सार्वभौमिक न होता, तो इसे अधिकार की श्रेणी नहीं रख पाते। इस समस्या पर विचार करते समय हमें पोषक तत्वों पर भी विचार करना चाहिये। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ हम सबके लिये पोषणता की सुरक्षा की मांग को अनदेखा नहीं कर सकते। सरकार द्वारा लोगों की खाद्य और पोषणता की सुरक्षा को पूरा करने के लिये राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।अन्यथा तथाकथित इस खाद्य सुरक्षा विधेयक को आगे लाने का कार्य निर्थरक साबित हो जायेगा। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक के आ जाने से गरिबों को खाद्यान्न देने की वर्तमान सुविधा भी घट सकती है और इस तरह खाद्य सुरक्षा और अधिक संकट में हो जायेगी। एक सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही इस समस्या का निवारण है, जो संप्रग सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण तैयार नहीं हो पा रही है।

जाने-माने खाद्य वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुये सही ही कहा है कि देश के अन्दर 1990-1992 में 21 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार रहे हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2004-2006 के मध्य 25 करोड़ 20 लाख के आस-पास हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया है कि पूरी दुनिया में अल्पपोषण के शिकार बच्चों की आधी आबादी भारत में रहती है। साथ में प्रति व्यक्ति कैलोरी की मात्रा में काफी गिरावट इधर के दशकों में देखी गयी है। एक तरफ खाद्यान्नों का पहाड़ और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों भूखे लोग दोनों का सह-अस्तित्व देखा जा रहा है।

सरकार खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक के वास्तविक स्वरूप को तय करने से पहले आवश्यक सुझावों पर ध्यान देना चाहिये। प्रस्तावित विधेयक में तीन तत्वों का समावेश होना चाहिये। (1) सबके लिये सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ; (2) एपीएल और बीपीएल तथा कम मूल्य पर गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना और ; (3) पोषण तत्वों के गारण्टी की सुरक्षा। हम यह मांग करते हैं कि प्रस्ताविक विधेयक तुरन्त पूरी तरीके से सुरक्षित हो और देश की आबादी को संतुष्ट करने के लिये खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिये लक्ष्य आधारित तीव्र कार्यक्रम भी निर्धारित हो।

बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) लोगों की कीमत पर आइपीएल क्रिकेट

जी. देवराजन

कभी क्रिकेट को भद्र लोगों का खेल कहा जाता था। परंतु अब अरबपतियों, फिल्मी सितारों, बड़े व्यापारी घरानों, शराब के कारोबारी, जमीन–जायदाद के करोबारी कम्पनियों, राजनीतिज्ञों और अवकाश प्राप्त महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के समूहों ने अपने काले धन को प्रयोग करने के लिये क्रिकेट हथियार बना लिया है। हाल में आईपीएल के उभरे विवाद से स्पष्ट हो गया कि इस पूरे खेल में काले धन का खुला प्रवाह हो रहा है और अमीरों का इस खेल से जुड़ाव जाहिर हो गया। यह भी जाहिर हुआ कि टीमों के मालिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा और खेलों को दूरदर्शन पर दिखाये जाने के अधिकारों को बेच कर धन बना रहे हैं। क्रिकेट से जुड़े सभी राज्य स्तरीय संघ और बीसीसीआई कहते रहे हैं कि मैचों को लाभकारी मात्र टिकटों की बिक्री से नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार भारी धन उगाही अन्य माध्यमों से किया जा रहा है।

अब हम देखें की विज्ञापनों के जरिये धन कैसे बनेगा और यह बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) जीने वाले लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा हैं? बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उपभोक्ता उत्पादों को दूरदर्शन पर दिखाने के लिये विज्ञापन बनाते हैं, उनके विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य आम जनता होती है, जैसे सौन्दर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने वाली कम्पनियां सुविधा संपन्न और क्रय क्षमता रखने वाले 20 प्रतिशत भारतीयों पर आंखें गड़ाये रहते हैं और भारत से सम्बन्धित विश्व सुन्दरियों को विज्ञापन के लिये चुनते हैं। आईपीएल के आयोजक मध्य वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों (बीपीएल) को निशाना बनाते है और क्रिकेट के द्वारा अपनी कमाई करते हैं। इन मैचों के दौरान दिखाये जाने वाले विज्ञापन खाद्य तेलों, कपड़ा धोने वाले पावडर, बच्चों के खाद्य उत्पाद, नैपकिन, नहाने साबुन, बाथरूम के सफाई से सम्बन्धित, मोबाईल फोन, ऑटोमोबाईल के होते हैं। वर्तमान भारतीय समाज उपरोक्त उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति अरूचिकर तरीके से उपभोग करने की सनक चढ़ी हुई हैं। इन उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति मध्य वर्ग के इस भावनात्मक लगाव को आईपील के आयोजककर्ता भलीभांति जानते हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इसके जरिये भारतीय बाजार पर हावी होने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत से लोग बार–बार कहते हुये देखे जाते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भारतीय बाजारों में प्रवेश करने में बुराई क्या है? यह एक सिद्ध तथ्य है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से जो यहाँ के उद्योग है ध्वस्त हो जायेंगे। पिछले दो दशक का अनुभव यह जाहिर करता है कि छोटे और ग्रामीण कुटीर उद्योग इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामने नहीं टिक सके और हजारों की संख्या में बंद हो गये। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उत्पादों को पहले अत्यंत सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराती है और ग्रामीण उत्पादों को समाप्त कर देती हैं। एक बार जब छोटे उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों का अवरोध समाप्त हो जाता है यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी कीमतों को बढ़ाने लगती है और बाजार को अपने हिसाब से चलाने के लिये आदेश देने लगती है। यह सत्य भारत के सभी गांवों और शहरों में देखा जा चुका है। यही नहीं यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कृत्रिम रूप से अशोभनीय, अरूचिकर उपभोक्ता संस्कृति का सृजन करती हैं, जिनसे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता हैं और पारिवारिक–सामाजिक नैतिक मूल्यों का तेजी से क्षरण होता है।

यह एक चौकानें वाला तथ्य सामने आया है कि केन्द्र सरकार और अनेक राज्य सरकारें इन आईपीएल मैचों के लिये करों में छूट दे रही हैं। आईपीएल को करों में छूट देने का अर्थ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को और पूँजिपति वर्ग को गरीब आदमी की कीमत पर छूट देने जैसा है। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएल मैचों के लिये मनोरंजन कर में छूट की घोषणा की, जो कि लगभग 10–12 करोड़ रुपये है। यहाँ तक अर्द्धनग्न चीयर लीडर्स (नाचती लड़कियां) को भी टैक्स में छूट है! यह तथ्य भी सामने आया है कि एक टीम के निर्माण में 1500 से 2500 करोड़ रुपये का खर्च आया है। बहुत से कारपोरेट घराने बिना नाम के आधार पर अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर शेयर रखते हैं। बहुत से आयोजकों ने टैक्स से बचने के लिये मॉरिशस में अपनी कम्पनियां पंजीकृत कराई है, बहुत से आयोजक अपनी प्रेमिकाओं को खुश करने के लिये और टैक्स बचाने में अपने शेयर इन्हें भेंट स्वरूप दिया है। सरकार एक मौन दर्शक है और इस तरीके की अनियमिततायें और काले धन का प्रवाह देख रही हैं। इस तरह आईपीएल हमारे देश के आर्थिक तंत्र को धोखा दे रही हैं और सरकार क्रिकेट के नाम पर इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अपना पूरा सहयोग दे रही हैं।

मुख्य धारा के प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया आईपीएल को खेल के विकास संबंधित सभी समस्याओं के निदान के रूप प्रस्तुत कर रहा हैं। जबकि इस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये इन टीमों से विज्ञापन प्राप्त करना इनका लक्ष्य हैं। इनमें से कुछ संचार माध्यमों ने कहना शुरू कर दिया है कि एक आईपीएल टीम संबंधित राज्य के मूलभूत ढाँचागत विकास में वृद्धि लायेगा। इस तरह यह संचार माध्यम राज्य को और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। एक क्रिकेट टीम किसी राज्य ढाँचागत विकास को कैसे ला सकती है? यह धन राज्यों को नहीं आ रहा हैं राज्यों में तो मैच टीमों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापनों से आ रही है। राज्य सरकार को तो मैच और टीमों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी पड़ रही हैं। राज्य सरकार को तो टीकटों की बिक्री के जरिये महज मनोरंजन कर लेने के नाम पर अपना पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक तंत्र प्रयोग में लाना पड़ रहा हैं। यह संचार तंत्र आईपीएल को अधिक समय प्रदान करते हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले आबादी के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिवद्धता को भूल गये हैं। बहुत से संचार तंत्र योजना आयोग के द्वारा स्वीकृत किये गये तेंदुलकर कमिटी की रिपोर्ट जो देश में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या से संबंधित है के प्रकाशन से बचते रहे हैं। शक्तिशाली मंत्रियों के समूह में यह स्वीकृत तथ्य है कि देश में इस समय 37.2 प्रतिशत बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) जीने वाले लोग है। यह तथ्य योजना आयोग के द्वारा संचालित सर्वेक्षण के आधार पर है। परन्तु यदि रेलवे पुलों के नीचे, ऊपरगामी पूलों के

नीचे और अस्थायी रहने वाले गरीबों को जोड़ दिया जाये तो यह संख्या बहुत बढ़ सकती है। संचार तंत्रों ने आईपीएल मैचों के दौरान जो कर में छूट मिले धनराशि का विवरण नहीं बताया और आर्थिक रूप से टूटे हुये गरीबों को खाद्य कितनी राहत मिलनी चाहिये ऐसा कोई विवरण नहीं प्रकाशित किया। इन संचार तंत्रों में आत्म हत्या करते किसानों (जो कर्ज के जाल में होते है के समाचार नहीं दिखाते हैं, बल्कि फैशन शो और आईपीएल मैचों के विभिन्न स्थलों पर पाँच सौ से अधिक मीडिया के लोग सदा उपस्थित रहते हैं।

सरकार संयुक्त संसदीय का गठन का आईपील मैचों हुये पूरे घोटलो और केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य चयनित प्रतिनिधियों की भूमिका की जाँच करवानी चाहिये। आईपीएल के दौरान आने वाले काले धन के स्रोतों की तहकीकात की जानी चाहिये। आईपीएल मैचों में प्रयोग किये गये इनके मालिकों और राजनेताओं के संबंधों की तुरन्त होनी चाहिये। भारत सरकार को आईपीएल मैचों के दौरान दिये गये सभी कर राहतों को वापस लेना चायिहे। सरकार को यह आवश्यस्त करना चाहिये कि आईपीएल मैच बीपीएल लोगों की कीमत पर कदापि नहीं होना चाहिये।

दंतेवाड़ा में हुई नृशंस माओवादी हमला: केन्द्र सरकार की नक्सल विरोधी नीति ने गहरी खामियाँ

पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ माओवादियों की समस्या से जूझ रहा है। अभी दंतेवाड़ा में घटित घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 76 जवानों की नक्सलियों द्वारा हत्या की घटना हुई। इस घटना में नक्सलियों ने 75 हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। जनता की मुक्ति के नाम पर हुई इस घटना को अलग नहीं देखा जा सकता।

कई राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय सीपीआई (माओवादी) अपनी गतिविधियाँ जारी रखे हुए हैं और वे करीब 220 जिलों में हिंसक गतिविधियों में लिप्त है। वे लूट, हत्या, फिरौती, स्कूलों को नष्ट करने और सड़कों के साथ-साथ संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि क्षेत्र के करीब गाँववासियों के अलावा सुरक्षा कर्मियों को हिंसा का शिकार बना रहे हैं। एक भी जमींदार, भूमाफिया और पूँजीपति उनकी हिंसा का शिकार नहीं हुआ। अनेक राज्यों में जारी माओवादियों की हिंसा पर केन्द्र सरकार का इसे संबंधित राज्यों की कानून व्यवस्था की समस्या कहना सरासर गलत है। माओवादियों की हिंसा से निपटने की प्रमुख जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की बनती है और उसे राज्य सरकारों के साथ ताल-मेल में कार्य करना चाहिए। जबकि अभी तक केन्द्र सरकार समस्या की जड़ तक पहुँचने में असफल रही है। केन्द्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में नि:संदेह राज्य, सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त कार्यवाही में अर्द्धसैनिक बलों का लगाया। परंतु इस समस्या के समाधान में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों की अलोचना से समस्या और ज्यादा जटिल हो गई और जनता को गलत संदेश पहुँचा। यह तथ्य नक्सल प्रभावित लालगढ़ में हुए केन्द्रीय गृहमंत्री के दौरे से स्पष्ट हुआथ था जबकि राज्य में कानून व्यवस्था के असफल रहने के लिये मुख्यमंत्री की तीखी आलोचना किया। गृहमंत्री को उकसाकर ऐसे बयान बाजी के पीछे और राज्य में उत्तेजक स्थिति उत्पन्न करने के पीछे कौन है यह सब पूरी तरह स्पष्ट है। एक केन्द्रीय मंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता ने खुले आम बयान जारी किया कि लालगढ़ में कहीं कोई माओवादी नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे छुपकर छद्म भेष में सीपीएम के कैडर है। सत्य से परिचित होने के बावजूद चिदम्बरम को ऐसे विवादास्पद बयानों से बचना चाहिये। परन्तु संप्रग सरकार की घटक पार्टी के आसन्न विधान सभा चुनाव के लिये निहित स्वार्थ के लिये ऐसा करना अशोभनीय है। परंतु, संपभवत: चिदम्बरम नहीं जानते थे कि इनके इन बयानों के दो दिनों बाद दंतेवाड़ा की नृशंस हत्या की घटना सामने आई। आरोपों के इस खेल का इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा।

ऐसे विषय परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्र और राज्यों के सत्तारूढ़ और विपक्ष दलों को नक्सलवाद से लड़ने की साझा रणनीति बनानी चाहिए जिस नक्सलवाद को प्रधानमंत्री ने स्वयं विकराल समस्या कहा है। सुरक्षाबलों के संयुक्त अभियान के साथ-साथ पूरे तत्परता के साथ स्थानीय विकास के कार्यक्रमों को चलाना चाहिए। ठीक ऐसे ही समय में हमें यह देखना होगा कि स्थानीय जनजातियाँ और गरीब तबके के लोग हिंसा, भूखमरी और तबाही के शिकार न बने। सभी गरीब जो कुछ काल के लिये नक्सलवादियों के बहकावें में आकर उनके पीछे खड़े होते हैं वे सभी नक्सवादी नहीं हैं। वे हमारे वर्ग दुश्मन नहीं हैं। जनजातियों और गरीब तबके के लोगों के विकास और मजबूत नक्सलवादी अभियान के साथ-साथ चलाते रहने से हम आशा करते हैं कि वर्तमान हिंसा के दौर से छुटकारा मिल जायेगा। इस दौरान वैचारिक रूप से हमारा संघर्ष सत्ता लोलुप गैर वामपंथी और अवसरवादी शक्तियों से वैचारिक संघर्ष जारी रखना होगा।

फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी का संदेश : एक मजबूत एवं गतिशील वाम नेतृत्व की आवश्यकता

2009 में कोलकाता में संपन्न अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर पार्टी ने नेताजी के रास्ते भारत के पुनर्निर्माण का शंखनाद किया था। 'भारत' से तात्पर्य प्रगतिशील बौद्धिक तत्वों की सक्रीय भागीदारी की सहायता से कामगार वर्गों के नेतृत्व के अधीन अनवरत संघर्ष के जरिये लक्ष्य निश्चित रूप से एक नया भारत बनाना है, जैसा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सपनों पर आधारित समाजवादी भारत होगा। गत शताब्दी के बीसवीं दशक के अंत से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारत में समाजवाद स्थापित करने की बहस शुरू कर दी, जिसे बाद में उन्होंने उसे भारतीय समाजवाद भारतीय रास्ते के रूप में विवेचना किया। भारत के रास्ते समाजवाद के लिये नया परिवर्तन की पहल से सुभाष चन्द्र का उदय भारतीय राजनैतिक क्षितिज पर एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में हुआ और उन्होंने एक मजबूत एवं गतिशील वाम नेतृत्व देश को दिया जो समाजवादी पुनर्निर्माण के रूप में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिये अनोखा सिक्का था, जिस पर आजादी प्राप्त करने के बाद देश में तत्काल पहल कदमी करने की जरूरत थी।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सम्मेलन के इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की पृष्ठभूमि में 2009 के दस्तावेज में विस्तार से उन कारणों का विश्लेषण किया था जिससे सत्ताधारी दल पूँजीशाही एवं साम्राज्यशाही शक्तियों से साठ-गाँठ कर और विस्तार से विवेचना किया था। जिस तरह से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा बताये गये समाजवादी पुनर्निर्माण के रास्ते वे भटक गये। 2009 के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्पष्ट निष्कर्ष था कि समाजवाद और पूँजीवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष और समाजवादी भारत की स्थापना के लिये जमीन तैयार करने के लिये जनांदोलन आज देश की पुकार है। अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर वाम एकता को बनाये रखने के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वाम एकता और जन विकल्प के लिए जब भी प्रयत्न किया जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक ने आगे बढ़कर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के एकनिष्ठ और बिना विचलन के विचारों के साथ उसमें शामिल होने और नई चुनौतियों का मुकाबला करने को तैयार है। पार्टी कभी भी साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों के साथ समझौता नहीं कर सकती।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की 2009 में संपन्न 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन के पश्चात् पहली केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग 2, 3, 4 अप्रैल 2010 को नई दिल्ली में हुई।

पार्टी अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर ने मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में देश की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों और पार्टी के सफलता पूर्वक संपन्न 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन के पश्चात् सांगठनिक कार्यों की चर्चा की गयी।

मीटिंग ने सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सीपीएम के वयोवृद्ध नेता साथी ज्योति बसु, एस.यु.सी.आई. के महासचिव साथी निहार मुखर्जी, वाम आन्दोलन एवं नक्सलबारी आंदोलन के वयोवृद्ध नेता साथी कानु सन्याल और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जी.पी. कोइराला को श्रद्धांजली दिया। इन दिवंगतों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया।

मीटिंग में गहन चर्चा के पश्चात् निम्नलिखित राजनैतिक प्रस्ताव पारित किये गये।

बजट - 2010-11

वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2010-11 का प्रस्तुत बजट समग्र विकास एवं मुद्रा स्फिति को रोकने के लिये अपर्याप्त था। उक्त बजट में कारपोरेट सेक्टर को अनेक प्रकार की सुविधायें, छूटें और करों में राहत दी गयी है। यह विरोधाभास है कि सरकार गरीबों को अनदेखा करके समग्र विकास की बात करती है। बजट में आयकर दाताओं को 26000 करोड़ रुपये की राहत दी गयी है तथा कारपोरेट क्षेत्र को 79,554 करोड़ रुपये की राहत दी गयी है। परन्तु वहीं यह सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिये मात्र 52,490 करोड़ रुपये की खाद्य छूट दे रही है। सरकार ने उत्पाद शुल्क को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की वृद्धि की है वहीं कारपोरेट कर 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। उत्पाद शुल्क में वृद्धि से कीमतें और बढ़ेंगी। ऐसे समय में वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अवहेलना करते हुये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कोई कोष आबंटन नहीं किया।

पहले से ही कृषि क्षेत्र समस्याओं से जुझ रहा है और बजट प्रस्ताव उसकी समस्याओं को और गम्भीर कर देगी। यूरिया के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि और उर्वरक में दी जाने वाली छूट में से 3000 करोड़ रुपये की कमी करने के निर्णय और उर्वरक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर से नियंत्रण हटाने से और अधिक किसान कृषि गतिविधियों से दूर होने के लिये बाध्य होंगे।

कच्चे तेल के ऊपर सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि के सरकार के निर्णय का व्यापक प्रभाव दिखेगा, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। इस शुल्क में बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये तक की वृद्धि होगी।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने भारत की आम जनता से अपील करती है कि वे गरीब-विरोधी और किसान-विरोधी बजट के प्रस्तावों के विरुद्ध

आवाज उठाने के लिये संघर्ष के लिये आगे आये।

रेलवे बजट 2010-11

रेलमंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2010-11 का रेलवे बजट महत्वाकांक्षी अवश्य है परन्तु तथ्यों पर आधारित नहीं है।

लगभग सभी योजनायें जिनमें नई सेवायें, सर्वेक्षण और लाईन्स (पटरी) शामिल है, को पुरा होने में वर्षों लगेंगे, क्योंकि इन कार्यक्रमों के लिये भारत सरकार के योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक है।

यह एक विरोधाभास है कि सरकार रेलवे का निजीकरण न करने की बात कहती है और वहीं माल गाड़ियों को चलाने के लिये निजी कम्पनियों को निवेश और छूट देने की बात करती है। अधिक से अधिक सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (च्च्च्) निवेश के तरीकों से बड़े स्तर पर भारतीय रेल के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

यात्री और माल भाड़े में वृद्धि न करने की घोषणा को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक स्वागत करता है, वहीं सरकार के नये सर्वेक्षणों और परियोजनाओं की महत्वकांक्षी घोषणायों को समयवद्ध पूरा करने की संभावना के प्रति संदेह करता है, क्योंकि रेलवे की वित्तीय दशा दयनीय है। बजट से यह स्पष्ट है कि रेलवे के पास उपलब्ध अतिरिक्त धन राशि 951 करोड़ रुपये की है, जो बहुत ही तुच्छ राशि है। मार्च 2010 तक शुद्ध राजस्व में कमी को देखते हुये अनुमानित बजट में तेज गिरावट देखी गयी है जो कि 8121 करोड़ से 6489 करोड़ रुपये कर दी गयी। वर्ष 2010-11 में रलेवे ने 3173 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित किया है, जिसमें 2,800 करोड़ रुपये विकास निधि के लिये और 373 करोड़ रुपये मूल निधि के लिये आबंटित किया गया हैं। इस तरह रेलवे की योजना 350 करोड़ रुपये बाजार से उधार लेने की है। उपर्युक्त तथ्यों से भारतीय रेल की वास्तविक स्थिति उजागर होती है। इस तरह वर्ष 2010-11 का रेलवे बजट तथ्यों पर आधारित नहीं है।

महिला आरक्षण विधेयक:

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक 9 मार्च 2010 को संसद की राज्य सभा में पास महिला बिल का स्वागत करता है। पार्टी का मत है कि यह निर्णय भारतीय संसद के इतिहास में सुनहरा अवसर था। कांग्रेस (आई) हमेशा से ही आम सहमति बनाने का एक खोखला बहाना बनाकर इस बिल को दरकिनार करती रही है। महिला आरक्षण के लिये वामपंथी पार्टियाँ लगातार संघर्ष और मांग कर रही थी, बेशक सरकार पर दबाव बनाने के लिये इसमें लम्बा समय लगा। वामपंथि पार्टियों ने इस बजट (प्रथम) सत्र के आरम्भ से इस बिल को पेश करने के लिये दबाव की अपनी रणनीति बना रखी थी, ताकि यह दुबारा से लम्बे समय के लिये टल न जाये। लेकिन परिस्थितियों में एक नया मोड़ आया जब कुछ सदस्यों ने संसद की कार्यवाही को रोकने का प्रयास करने के लिये उग्र प्रदर्शन किया और बिल पेश न किया जाये इसके लिये धरने पर भी बैठ गये। फिर भी पार्टी का मत है कि केवल संसद और विधान सभा में सीटों का आरक्षण आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप उनके सशक्तिकरण के लिये पर्याप्त नहीं है। सशक्तिकरण इस आरक्षण का मूल उद्देश्य होना चाहिये, और हमें अन्य कारकों में भी समान अवसर देकर इन्हें सच्चे अर्थों में सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

नागरिक जवाबदेही परमाणु विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं :

संप्रग-द्वितीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में आकर नागरिक जवाबदेही परमाणु विधेयक को लाने की फिराक में है। नुकसानदेह परमाणु नागरिक जवाबदेही विधेयक में परमाणु संयंत्रों में होने वाले दुर्घटना के लिये परमाणु संयंत्र आपूर्तिकर्ता और संयंत्र आपरेटर हमें लूटने के चक्कर में है। अमेरिकी प्रशासन ने यह शर्त भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में रखी है। नागरिक जवाबदेही परमाणु विधेयक से विदेशी रियेक्टर आपूर्तिकर्ताओं खराब संयंत्र आपूर्ति करके या घटिया संयंत्र की आपूर्ति करके कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। परमाणु दुर्घटना होने पर वित्तीय जवाबदेही घटाकर 2142.85 करोड़ रुपये किया गया है। इस सौदे से प्रभावित लोगों को उनके जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति की हानि होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसका एक और आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि परमाणु संयंत्रों के भारतीय आपरेटरों का दायित्व मात्र 500 करोड़ रुपये का होगा। केन्द्र सरकार इसे घटाकर 100 करोड़ रुपये तक भी कर सकती है! भारत सरकार अर्थात भारत की जनता 2142.85 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये का अंतर 1642.85 करोड़ रुपये का दायित्व वहन करेगी।

नागरिक जवाबदेही परमाणु विधेयक एक ऐसा हथियार है जो परमाणु संयंत्रों के निजीकरण को बढ़ावा देगा विशेषकर अमेरिका के परमाणु कम्पनियां, जिन्हें कम खर्चे और कम जोखिम पर अधिक मुनाफा देगा। यदि इस विधेयक को इसकी वर्तमान दशा में स्वीकार कर लेते हैं तो यह देश के लिये हानिकारक होगा। अत: जनता को भी इस विधेयक के विरोध में आवाज उठाना चाहिये।

पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण :

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, रंगनाथ मिश्र आयोग की प्रमुख अनुशंसा के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुये मुस्लिमों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय का स्वागत करता है। जैसा कि गणना की गयी है मुस्लिमों का अन्य पिछड़ा वर्ग 16,38,000 है जो पश्चिम बंगाल के अन्य पिछड़े वर्ग की कुल आबादी का 8.3 प्रतिशत भाग है। पश्चिम बंगाल अन्य पिछड़े वर्ग में 66 संप्रदाय है, जिनमें मुस्लिमों के 12 वर्ग है। सरकार के निर्णय के अनुसार जिन लोगों की वार्षिक आय 4,50,000 से कम है, वे आरक्षण के हकदार है। मलाईदार तबके को इस आरक्षण सीमा से बाहर कर देना उचित है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक उक्त निर्णय को पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की दशा को उजागर करने वाले

सच्चर आयोग के द्वारा प्रस्तुत दयनीय दशा को सुधारने के दृष्टिकोण से देखती है और बिना किसी प्रशासनिक अज्ञानता और रूकावट के इस निर्णय को पश्चिम बंगाल सरकार से लागू करने की अपील करती है।

यह बहुत ही गंभीर चिन्ता का विषय है कि सचर कमिटी के रहस्योद्घाटन के पश्चात् तथा कई राज्यों की सरकारों द्वारा पहल के बाद भी केन्द्र सरकार ने रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों पर अपराधिक चुप्पी बना रखी है। यहाँ तक कि संप्रग सरकार इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत भी नहीं कर रही है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सरकार से अनुरोध करती हैं कि इस रिपोर्ट को लागू करने के लिये तत्काल कदम उठाये।

बीटी ब्रिंजल (जैव प्रौद्योगिकी बैंगन)

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने बीटी ब्रिंजल के व्यापारिक कृषि उत्पादन पर मानव स्वाथ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययनों के आने वाले तथ्यों तक केन्द्र सरकार के पीछे हटने के कदम का स्वागत करता है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक किसानों के उत्पाद और आजीविका में वृद्धि लाने के लिये कृषि क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान और तकनिक के प्रयोग के पक्ष में है। परन्तु यह प्रयोग हमारे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सतत् सुरक्षा के दृष्टि से होना चाहिये। पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि आधुनिक तकनीक लाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारतीय कृषि के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित नहीं बर्दाश्त की जा सकती है और इस तरह राष्ट्र के जैविक संसाधन पर राष्ट्र का सार्वभौम अधिकार होना चाहिये, न कि कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निजी निवेश को प्राप्त होना चाहिये। परन्तु यह चिन्ता का विषय है कि कृषि क्षेत्र में भारत-अमेरिका में ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु बोर्ड में मोंसेंटो और वाल मार्ट के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जो भारतीय किसानों के हितों के लिये हानिकारक हैं।

भारत-पाक वार्ता

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक भारत और पाकिस्तान की सरकारों के मध्य शेष मामलों को निपटाने क लिये होने वाली वार्ता के संदर्भ में लिये जाने वाले उपायों का स्वागत करता है। हमारा यह मत है कि वार्ता की प्रक्रिया चलनी चाहिये परन्तु यह भारत सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि इस वार्ता के संचालन में पड़ने वाले अमेरिकी दखल और दबाव के संदर्भ में वह स्पष्टीकरण दे। यदि कहीं से भी अमेरिकी दबाव इस द्विपक्षीय वार्ता के ऊपर है तो वह भारतीयों हितों पर आघात पहुँचायेगा।

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव

महिन्दा राजपक्षे श्रीलंका के पुन: राष्ट्रपति चुने गये। उन्होंने पूरे विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सरत फोंसेका को हराया। यह आरोप लगाये कि उक्त चुनाव में सरकारी गठजोड़ ने धाँधलेबाजी की है। इस प्रकार की जीत प राजपक्षे की नीतियों और कार्यक्रमों को जनादेश मिल गया, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। श्रीलंका के लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोषण के शिकार अभी भी है और अपने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस परिदृश्य में उदाहरण के रूप में दयनीय तमिल लोगों की परिस्थितियों को देखा जा सकता है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और देश प्रेम दिवस

23 जनवरी 2010, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का 114वां जन्मदिन अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं और नेताजी के अनुयायियों द्वारा पूरे देश में मनाया गया।

इस अवसर पर रैलियों, सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, बहस, कला और खेल के जरिये संकल्प ग्रहण समाराहों आदि का आयोजन किया गया। इस वर्ष फारवर्ड ब्लॉक के साथ तीनों वामपंथी पार्टियों – सीपीएम, सीपीआई और आरएसपी – ने केन्द्र सरकार से संयुक्त रूप से आग्रह किया कि 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित किया जाये। यह सुझाव 1997 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नेताजी जन्म शताब्दी समारोह समिति (बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमिटी) ने भी सुझाया था। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का विचार है कि यह घोषणा नव-युवकों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिये बहुत ही आवश्यक है।

23 जनवरी को देश प्रेम दिवस की घोषणा के लिये संसद में राज्य सभा में हमारे केन्द्रीय सचिव मण्डल सदस्य साथी डॉ. बरूण मुखर्जी ने 17 दिसम्बर 2008 को यह बात उठाई थी जिसके संदर्भ में योजना एवं संसदीय कार्यवाही राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री नारायसामी ने अपने पत्र संख्या एफ.3-10/2010-सी एंड एम दिनांक 16 मार्च 2010 में जवाब देते हुये कहा कि "आपके द्वारा दिये गये सुझाव पर सांस्कृतिक मंत्रालय में विचार विमर्श किया गया। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिनके योगदानों का गिनाया नहीं जा सकता। इस प्रकार किसी भी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति की सालगिरह को घोषित नहीं किया जा सकता, अत: 'देश प्रेम दिवस' की घोषणा संभव नहीं है। यहाँ तक की महात्मा गाँधी के जन्म दिवस को देश की स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में घोषित नहीं किया गया है। अत:, इस स्तर पर आपका अनुरोध संभव नहीं है।"

इससे स्पष्ट होता है कि सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बलिदानों को साधारण समझती है, जबकि महात्मा गाँधी ने भी स्वयं ही नेताजी को 'देशभक्तों का देशभक्त' कहा था। फारवर्ड ब्लॉक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सैकड़ों देश भक्तों की कद्र करता है। लेकिन नेताजी का नाम जनता में विशेष युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिये आता है।

कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के मुखौटे को हटाने के लिये फारवर्ड ब्लॉक की नेताजी के प्रति इस उदासीन रवैये को उजागर करेगा। फारवर्ड ब्लॉक 22 जून 2010 से 28 जून 2010 तक राष्ट्रव्यापि आंदोलन करेगा।

पार्टी स्कूल:

नेताजी का भारत निर्माण के लिय पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं जनांदोलन हेतु प्रशिक्षण देने के लिये 'राजनैतिक सुभाष स्कूल (सुभाष स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स)' की स्थापना की जाये। जिसके आरम्भिक चरण में पार्टी सदस्यों के नियमित प्रशिक्षण के लिये हम तीन स्थायी सुभाष स्कूल की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें दक्षिण क्षेत्र(केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश), उत्तर-केन्द्र क्षेत्र (हिन्दी भाषयी क्षेत्र) और पूर्व क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, और उत्तर-पूर्व के के राज्य) है। इस वर्ष 10 प्रतिशत सदस्यों को प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त होगा।

आन्दोलनात्मक कार्यक्रम

राष्ट्रीय सम्मेलन में जनांदोलन कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया था। बिना जनांदोलन के पार्टी का विकास असंभव है। अत:, जमीनी स्तर से हमें जनांदोलनों को बढ़ाना होगा

बुनियादी कार्य :

(क) 'नेताजी के सपनों का भारत का पुनर्निर्माण, नेताजी का भारत एक समाजवादी भारत' का प्रचार।

(ख) नेताजी का जन्म दिन 'देश प्रेम दिवस' घोषित किया जाये और एक्शन टेकन रिपोर्ट खारिज किया जाये तथा मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की जाये, के लिये अभियान तेज करना।

(ग) अँग्रेजी के सी-4 (करप्पशन, क्रिमिलाईजेशन, कम्युनिज्म, कम्युनल) भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, साम्प्रदायवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष।

(घ) नव-साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष।

(ङ) भूमी खेत जोतने वाले को।

(च) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगूल से भूमि, पानी और जंगल की रक्षा करना।

मांगें

(1) कृषि, कुटिर उद्योग और लघु उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश रोकों।

(2) कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य।

(3) किसानों को 4 प्रतिशत की दर से संस्थागत ऋण।

(4) कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार पर रोक लगाई जाये।

(5) कृषि मजदूरों के लिये केन्द्रीय कानून।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक किया जाये।

(7) परियोजनाओं के पूर्व जनता/ग्राम सभा से विचार विमर्श किया जाये।

(8) विस्थापितों के लिये पुनर्वास किया जाये तथा व्यापक पुनर्वास कानून बनाया जाए।

(9) खनन क्षेत्रों का निजीकरण नहीं होना चाहिये, निजीकरण और आउट सोर्सिंग के तहत ठेकेदारी बंद करो।

(10) 14 वर्ष की आयु तक सबको उत्तम और नि:शुल्क शिक्षा दिया जाये।

शिक्षा का व्यवसायिकरण और निजीकरण बंद करो।

(11) सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था अवश्य हो।

स्वास्थ्य - शिक्षा सबका अधिकार।

(12) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 200 दिन तक नरेगा के तहत सभी को रोजगार।

(13) महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण बिल उसके मूल स्वरूप के साथ तुरन्त पास किया जाये।

(14) रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट अमल में लाई जाये।

नेताजी सुभाष फाउण्डेशन:

इस वर्ष 21 अक्तूबर तक "नेताजी के रास्ते भारत का पुनर्निर्माण" के अभियान के लिये हमें मजबूत मंच तैयार होगा। नेताजी सुभाष फाउण्डेशन सभी राज्य में स्थापित करेंगे। केन्द्र से साथी सुब्रत बोस इसकी जिम्मेवारी लेंगे। सभी राज्य कमिटियों से अनुरोध है कि साथी सुब्रत बोस की सभी प्रकार से सहयोग करें।

कार्यशाला :

नई दिल्ली में मई माह के दौरान एक राष्ट्रीय कार्यशाला-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें किसान - कृषि श्रमिक, आदिवासी - वन श्रमिक भाग लेंगे।

देश प्रेम और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए नागरिकों का कन्वेंशन

महान क्रान्तिकारी देशभक्त नेता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जीवन एवं संग्राम दशकों से देशवासियों के लिये प्रेरणा दायक रहे हैं। सभी देश वासियों के लिये दिलों में वे महान नेता के रूप में याद किये जाते है। उनका सर्वोच्च बलिदान और देश के लिए उनका प्यार भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में काफी विरले उदाहरण है। गाँधी जी ने नेताजी के प्रति अपनी भावना का उल्लेख करते हुये उन्हें "देश प्रेमियों में देश प्रेमी" के खिताब से नवाजा था। आधुनिक भारत में नेताजी का नाम देश भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सुभाष चन्द्र ने अपने बहुतेरे सांसारिक सुखों एवं अभयुदय को तिलांजलि दे दी थी। जैसे - भारतीय सिविल सेवा की नौकरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद तथा आजादी के बाद ऊँचे महत्त्वपूर्ण पदों के लोभ को त्याग दिया और कष्टों भरी जिन्दगी जीना स्वीकार किया जिसमें ग्यारह बार अंग्रेजों की जेल यातना तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण देश से महानिष्क्रमण की यात्रा अपने को साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को जारी रखने के लिये सहन किया। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम आजादी के बाद के युगों में भी उन्हें समुचित मर्यादा सरकारी तौर पर देने में विफल रहे। इसलिए भारत की जनता लंबे समय से मांग कर रही है और सरकार से निवेदन कर रही हैं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को सरकार 'देश प्रेम दिवस' देश-भक्ति के दिन को सरकारी रूप में घोषित करें। जिस तरह से देश के बहुत से ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म दिनों जैसे डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जवाहर लाल नेहरू, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा गाँधी, प्रशांत महानवील को समुचित सम्मान दिया गया है।

इस मांग की अनिवार्यता वर्तमान दशक के परिपृष्ठ में और अधिक बढ़ जाती है जब हमारे देश की युवा पीढ़ी में देश भक्ति की भावना को पूर्ण रूप से समाहित करने की जरूरत है। एक बार जब हम स्कूल एवं कॉलेजों में नेताजी का जन्म दिवस देश प्रेम दिवस के रूप मे मनाना प्रारंभ कर देंगे तो इससे हमारी नई पीढ़ी के बीच में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना की प्रेरणा मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय विकास में भी यह सहायक होगा। हाल के दिनों में यह महसूस किया जा सकता है जबकि मुख्य रूप से हमारे देश वासियों में हताशा की भावना के कारण उनमें देशभक्ति की भावना का अभाव का सृजन हुआ है, जिसका कारण आम आदमी की दयनीय आर्थिक स्थिति है। वैसी परिस्थिति में नेताजी के ऐतिहासिक जन्म, दिवस पर जनता का आह्वान किया जा सकता है कि उनमें पुनः एक बार देश भक्ति की भावना का उदय हो सके। नेताजी की देशभक्ति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के उदाहरण से हमें एकजूट होकर काम करने में सहायक होगा और देश को गरीबी उन्मूलन के जाल से बाहर करने में मदद मिलेगी और उस देश भक्ति की भावना को बल मिलेगा जिसके लिये उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया था।

इन्हीं विचारों को अपने मन में रखकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा संस्थापित पार्टी फारवर्ड ब्लॉक के साथ-साथ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के करोड़ों अनुयायी एवं समर्पित कार्यकर्ता नेताजी के जन्म दिवस को लंबे समय से देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हुए सरकार से मांग करती है कि वह सरकारी तौर पर उसे देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित करे। इस दिशा में यह भी स्मरण कराना उचित होगा कि वर्ष 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार की अगुयायी में गठित नेताजी जन्म शताब्दी समारोह समिति ने भी 23 जनवरी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित किया था। बाद में केन्द्र की चार वामपंथी पार्टियों के केन्द्रीय नेतृत्व माकपा, भाकपा, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने भी संयुक्त रूप से 31 दिसम्बर 2009 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखित रूप से आग्रह करते हए भारत सरकार से 23 जनवरी नेताजी जन्म दिवस को देश-प्रेम दिवस के रूप में घोषित करने की अपील एवं अनुरोध किया था, लेकिन इस बहरी, कांग्रेस सरकार के कानों में इस अपील एवं अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक भारत सरकार से कोई विभागीय जवाब भी नहीं दिया गया। जबकि बहुत से लोगों द्वारा लंबे समय से प्रदर्शनों, मांगों, अपील अनुरोध भी इस संबंध में किया गया।

अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए पहली सरकारी प्रतिक्रिया डॉ. बरूण कुमार मुखर्जी, सचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक एवं सांसद राज्य सभा को उनके द्वारा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के जरिये 17 दिसम्बर 2008 को उठाये गये आग्रह के सवाल कि 'सरकार 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित करे', लेकिन इस विशेष उल्लेख के जरिये उठाये गये सवाल का जवाब 16 मार्च 2010 को दिया गया योजना एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नारायणसामी ने उनके पत्र संख्या एफ-3-10/2010-सी.एण्ड.एम/590 दिनांक 16 मार्च 2010 के द्वारा कहा कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा विचार किया गया जिसमें तमाम विशिष्ट व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिये थे और उनके साथ अपेक्षात्मक न्याय नहीं किया गया। यदि ऐसे सभी दिनों को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित किया जाये तो प्रत्येक दिन को देश प्रेम दिवस घोषित करना पड़ेगा। परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति के जन्म दिन को किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम से घोषित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि महात्मा गाँधी के जन्म दिवस को भी किसी विशेष दिवस के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विशेष दिवस के रूप में घोषित नहीं किया गया। आपके अनुरोध को इस समय सवीकृति प्रदान करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपके इस अनुरोध पर सरकार का सहमत होना संभव नहीं है।

इससे प्रतीत होता है कि सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और देशभक्ति को भी सामान्य तौर पर देख रही है।

जबकि महात्मा गाँधी ने भी नेताजी को देशभक्तों में देशभक्त के अलंकरण से विभूषित किया था। फारवर्ड ब्लॉक कभी भी आजादी के उन लाखों दिवानों को बलिदानों को कभी भूला नहीं सकती है और न उसे कम करके आकलन करती है लेकिन नेताजी का नाम ही देशभक्ति की भावना का उर्जा स्त्रोत एवं आम जनता के लिये प्रतीक चिन्ह बन चुका है। खासकर उस महान भावना की कमी है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उपर्युक्त वर्णिति पत्र में जोर दिया है कि यदि महात्मा गाँधी के जन्म दिन को किसी विशेष दिवस के रूप में घोषित नहीं किया गया है। लेकिन विद्वान मंत्री महोदय ने काफी चतुराई से इस मामले को दर किनार कर दिया कि महात्मा गाँधी एकमात्र राष्ट्रीय नेता को और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया।

यद्यपि हम राष्ट्रीय नेताओं के बीच इस तरह का कोई तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम यह अवश्य कहना चाहेंगे कि भारत सरकार नेताजी को उचित सम्मान देने में विफल रही है। लेकिन यह भी दुर्भाग्य पूर्ण है कि इस संवेदनशील मसले पर सरकार आम जनता को गुमराह कर रही है।

अत: हमलोग दशकों से लंबित इस मांग पर नागरिक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, ताकि अधिकाधिक जनता का ध्यान एवं समर्थन इस मसले में जुटाया जाये। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन को देशप्रेम दिवस के रूप में घोषित किया जाना समय की आवश्यकता है। हम उन महान देशभक्तों के प्रति कोई कृपा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने को एक नये भारत-एक मजबूत भारत-आधुनिक भारत के निर्माण के लिये परिपूर्ण कर रहे हैं।

इस महान नागरिक सम्मेलन के जरिये हम भारत सरकार से पुन: आग्रह करते हैं कि नेताजी के जन्म दिन को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित करने की दिशा में हमारे देशभक्त युवाओं की भावनाओं को पुन: प्रेरणा प्रदान कर प्रगतिशील की अवधारणा को मजबूत किया जाये।

टीयूसीसी का गांव-गांव का दौरा करने का ऐलान

कानपुर 26 अप्रैल 2010 ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेन्टर (टी.यू.सी.सी.), उत्तर प्रदेश राज्य समिति की बैठक रामनारायण जोरवीराम धर्मशाला कानपुर में साथी हंसराज अकेला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि साथी एस.पी. तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव टीयूसीसी ने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि आज भीषण महँगाई के अलावा श्रम कानूनों का देश में पालन न होना आदि कारणों से श्रमिकों का जीना दूभर होता जा रहा है। इसके लिये टीयूसीसी की तरफ से गांव-गांव में श्रमिकों को जागरूक करके उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना होगा।

बैठक में इस वर्ष जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशनों पर चर्चा हुई। अधिवेशनों के पूर्व बीड़ी श्रमिक यूनियन अल्प असंगठित क्षेत्र की यूनियनों को गठित करने का प्रस्ताव भी लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मई व जून में अधिक से अधिक जिलों में प्रदेश के पदाधिकारी दौरा करके श्रमिकों को जागरूक करके उनकी समस्याओं को लेकर 28 जून को लखनऊ विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। इस मौके पर साथी एस.पी. तिवारी, भी उपस्थित रहेंगे।

बैठक में मध्य प्रदेश टीयूसीसी के महासचिव साथी संजय यादव एवं उत्तर प्रदेश के साथी महेन्द्र सिंह, डॉ. हरीश गुप्ता, साथी उदय मान सिंह, साथी सतपाल, साथी लालता प्रसाद, साथी हरिहर विजय पाल, साथी हरीराम एवं उत्तर प्रदेश फारवर्ड ब्लॉक राज्य महासचिव साथी शिव नारायण सिंह चौहान भी उपस्थित थे।

महँगाई के खिलाफ एवं खाद्य सुरक्षा के लिये राष्ट्रव्यापि धरना और जेल भरो आन्दोलन

देश भर में धरना प्रदर्शन करने और गिरफ्तारी देने वाले उन लाखों जनता को वामदल बधाई देती है। मूल्य वृद्धि, भूमि, रोजगार और पश्चिम बंगाल में वामपंथियों पर हो रहे लगातार हमले के खिलाफ वामदलों द्वारा उठायी जा रही मांग के समर्थन में था।

विभिन्न राज्यों से मिली रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25 लाख लोगों ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया तथा गिरफ्तारियाँ दी।

नई दिल्ली: फारवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीआई (एम) और आरएसपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने 8 अप्रैल 2010 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में महँगाई के विरुद्ध व खाद्य सुरक्षा के लिये प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी कालाबाजारियों और अनाजों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के जमाखारों को दण्ड देने का नारा लगा रहे थे तथा वे मांग कर रहे थे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक किया जाये, अनाजों के वायदा कारोबार बन्द किये जायें, जरूरतमंतों को सस्ते दर राशन उपलब्ध कराया, भूमिहिनों को भूमि दिया जाये और बेघरों को घर उपलब्ध कराया जाये।

सत्याग्रहियों को साथी देवब्रत बिश्वास (महासचिव फारवर्ड ब्लॉक), साथी ए.बी. वर्द्धन (महासचिव सीपीआई), साथी प्रकाश करात (महासचिव

सीपीएम) और साथी अबनी रॉय (सचिव आरएसपी) ने सम्बोधित किया। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि से आम जनता का जीवन जीना दूभर हो गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड के जारी करने में भारी अनियमितता है, गरीब जिन्हें इनकी आवश्यकता है वे इधर-उधर भटक रहे हैं। यह मांग कि की जरूरतमंदों को सस्ते राशन उपलब्ध कराया जाये। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही मुख्य मुद्दा है, लेकिन सरकार इसके लिये कोई भी आवश्यक कदम उठा नहीं रही हैं। किसानों की समस्या के समाधान के लिये सिंचाई, बीज और उर्वरकों में अधिक से अधिक अनुदान दिये जाने की मांग की और उनके उत्पादों और अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने की भी मांग की गयी। वायदा कारोबार बन्द किया जाना चाहिये। वक्ताओं ने कहा कि भूमि सुधार गम्भीरता से लागू होना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं में सुधार आयेगा। उन्होंने मांग किया की बेघर को घर दिया जाये तथा उनके लिये स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

सभा के बाद, चारों वामदलों के नेताओं ने गिरफ्तारी दी। अन्य सत्याग्रहियों में मुख्य रूप से साथी डी.राजा, सांसद, साथी अमरजीत कौर, साथी पुष्पिंदर ग्रेवाल, साथी दिनेश वारशने, साथी विजेन्द्र शर्मा, साथी आसित गांगुली और साथी धमेन्द्र वर्मा सहित लगभग 6 हजार लोगों ने गिरफ्तारी दीं। पुलिस ने जिन्हें तितर-बितर करने के लिये पानी बौछारें की।

पश्चिम बंगाल : 8 अप्रैल 2010 पश्चिम बंगाल के कोलकाता तथा अन्य जिलाओं में लगभग 10 लाख लोगों ने धरना दिया। सभी वामपंथी पार्टियों के संयुक्त आह्वान पर पूरे राज्य में महँगाई विरोधी धरने का मंचन किया गया। कोलकाता के एस्पलानेड स्थित मुख्य आयकर कार्यालय पर पूरे दिन लगभग 1 लाख लोगों ने धरना दिया। इस विशाल जन सभा को साथी बिमान बोस, वाम अध्यक्ष, सीपीएम नेता साथी बिनोय कोनार और साथी रोबिन देब, फारवर्ड ब्लॉक नेता साथी (डॉ.) बरूण मुखर्जी और साथी हाफिज आलम सैरानी, आरएसपी नेता साथी मनोज भट्टाचार्य, सीपीआई नेता साथी मंजु मजुमदार और अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

कार्यक्रम के अंत में साथी अशोक घोष, फारवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल राज्य महासचिव ने एक वक्तव्य जारी करते हुये संप्रग सरकार की जारी रही बढ़ती महँगाई और जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ 8 अप्रैल के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी जनमानस का शुक्रिया अदा किया। साथी घोष ने आगे कहा कि इस दिन का कार्यक्रम भविष्य में की ओर संकेत है कि इस प्रकार के कार्यक्रम और भी किये जायेंगे तथा तृणमूल कांग्रेस द्वारा वामदलों के खिलाफ रचे जा रहे षड्यन्त्र के खिलाफ कार्यक्रमों के आयोजन होते रहेंगे। इसके अलावा साथी अशोक घोष ने पश्चिम बंगाल के जन्य जिलों फारवर्ड ब्लॉक कार्यकर्ताओं के भागीदारी को भी बताया जो इस प्रकार थी : कूच बिहार-20000, जलपाईगुड़ी-3000, दक्षिण दिनाजपुर-3000, बिरभूम-25000, बांकुरा-25000, पश्चिम मिदनापुर-30000, हूगली-2000, कोलकाता-5000, पुरूलिया-20000।

केरल : 8 अप्रैल 2010 को वामदलों द्वारा आयोजित जेल भरो आन्दोलन में केरल के पूरे राज्य में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रमों का सफल आयोजन लेफ्ट डेमोक्रेटिंग फ्रंट ने किया। एलडीएफ ने अधिकारिक रूप से फारवर्ड ब्लॉक के नेताओं को निमन्त्रित किया। जिसमें साथी जी. देवराजन, राष्ट्रीय सचिव फारवर्ड ब्लॉक ने तिरूवनंतपुरम में नेडुमंगड पोस्ट ऑफिस के सामने प्रदर्शन का उद्घाटन किया तथा प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। साथी टी.जे. चन्द्रचूड़न, महासचिव आरएसपी, ने पाथमथिट्टा में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथी वाइको विशवन, एलडीएफ संयोजक ने त्रिवेन्द्रम में मुख्य पोस्ट मास्टर आफिस पर मोर्चा संभाला। साथी वी. राम मोहन, महासचिव केरल राज्य कमिटी फारवर्ड ब्लॉक ने साथी वाइको के साथ त्रिवेन्द्रम में प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। साथी थंकचन वर्गीस (ओल्लुर-त्रिसुर), साथी के. आर. ब्रह्मानन्दन (चथनूर-कोल्लम), साथी अरूण एस. साशी (तिरूवनंतपुरम), साथी हुमांयु कबीर (कोझिकोड), साथी एम. विजयन (कंजागड़) साथी अब्दुल कादेर वझाकाल्ला (कोची), साथ कलाथील विजयन (अलापुझा), साथी राजन कूदाली (कन्नूर), साथी थाम्पी (पुन्नाथाला (कोल्लम मुख्य पोस्ट ऑफिस), साथी रंजीत राजेन्द्रन (आरएमएस - तिरूव- नंतपुरम), साथी थोट्टुवा सुरेन्द्रन (करूणागापल्ली), एडवोकेट पी.ए. रॉय (चलाकुड्डी), साथी के.वी. भद्रन (वेल्लाराडा), साथी एम. सुधाकरण (बथेरी - व्यानाडु) आदि ने भी प्रदर्शन और धरने को विभिन्न स्थानों पर संबोधित किया और गिरफ्तारी दी। नेदुमनागद में प्रदर्शन का उद्घाटन करते हुये साथी जी. देवराजन ने उपस्थित लगभग 4000 लोगों को सामने उन तथ्यों का उजागर किया जिसके कारण वामदलों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया। केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ती कीमतों को रोकने में असफल रहने पर और कृषि के प्रति बेरूखी रवैये की घोर आलोचना की। स्थानीय सीपीआई विधायक साथी मंगोड राधाकृष्णन और साथी एस.के. अचारी (सीपीएम) और अन्य एलडीएफ के नेताओं ने संबोधित किया।

तमिलनाडु : राज्य में 8 अप्रैल 2010 को तीन वामपंथी दलों सीपीएम, सीपीआई और फारवर्ड ब्लॉक द्वारा आयोजित जेल भरो आन्दोलन में भाग लिया। तमिलनाडु के 20 जिलों में जिला कमिटियों ने जिला कार्यालयों पर बड़े ही जोश-खरोश के साथ भाग लिया। साथी वी.एस. नवामनी, अध्यक्ष तमिलनाडु राज्य कमिटी फारवर्ड ब्लॉक ने विरूधुनगर के जिला कार्यालय पर भाग लिया, जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं क साथ प्रदर्शन किया और उन्हें संबोधित किया।

मुख्य पोस्ट ऑफिस के लिये रैली का आरम्भ विरूधुनगर में किया गया जिसमें लगभग हजारों कार्येकर्ता थे जिसे पुलिस ने रोक दिया और गिरफ्तार किया।

चेन्नई में हजारों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया जिन्हें साथी पी.वी. कादीरवन (राष्ट्रीय सचिव फारवर्ड ब्लॉक व महासचिव तमिलनाडु राज्य कमिटी), साथी डी. पाण्डीयन (सीपीआई), साथी जी. रामाकृष्णन (सीपीएम) ने संबोधित किया तथा गिरफ्तारी दी।

त्रिपुरा : राज्य में लगभग 1,50,000 वामदलों के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आन्दोलन, आवश्यक बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने और रोजगार के लिये किये जा रहे कार्यक्रम के तहत वाम समर्थित राज्य में गिरफ्तारी दी।

चारों वामपंथली दलों - सीपीएम, सीपीआई, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी - ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया तथा प्रेस विज्ञप्ति दिया का सरकार तुरन्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान करे, भूमि सुधार कानून लागू करे तथा महँगाई पर लगाये। त्रिपुरा राज्य कमिटी फारवर्ड ब्लॉक महासचिव साथी

श्यामल रॉय ने अगरतला में तथा अध्यन फारवर्ड त्रिपुरा राज्य कमिटी साथी ब्रज गोपाल रॉय ने धरमतला में गिरफ्तारी दी।

उत्तर प्रदेश : फारवर्ड ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अन्य वामदलों के साथ संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय कार्यालयों पर प्रदर्शन किया तथा गिरफ्तारी दी। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग कि की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाये। लेकिन सरकार इसके लिये कोई भी आवश्यक कदम उठा नहीं रही हैं। किसानों की समस्या के समाधान के लिये सिंचाई, बीज और उर्वरकों में अधिक से अधिक अनुदान दिये जाने की मांग की और उनके उत्पादों और अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने की भी मांग की गयी। वायदा कारोबार बन्द किया जाना चाहिये। वक्ताओं ने कहा कि भूमि सुधार गम्भीरता से लागू होना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं में सुधार आयेगा। उन्होंने मांग किया की बेघर को घर दिया जाये तथा उनके लिये स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

आन्ध्र प्रदेश : फारवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीआई (एम) और आरएसपी के लगभग 50000 कार्यकर्ताओं ने 8 अप्रैल 2010 महँगाई के विरुद्ध व खाद्य सुरक्षा के लिये प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग कि की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाये, वायदा कारोबार बन्द किया जाये, महँगाई पर रोक लगाई जाये। पुरे राज्य में फारवर्ड ब्लॉक के मुरलीधर राव देशपाण्डे सहित, सीपीएम और सीपीआई के नेताओं कार्यक्रम को संबोधित किया तथा गिरफ्तारी दी।

झारखण्ड : चार वामदलों भाकपा, माकपा, फारवर्ड ब्लॉक एवं आरएसपी द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी जेलभरों कार्यक्रम के तहत 8 मार्च 2010 को साथी जनार्दन पाण्डेय प्रांतीय महासचिव के नेतृत्व में रांची में राजभवन के समक्ष सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी जिसमें साथी साथी उमाशंकर पाण्डेय, साथी नूर मोहम्मद प्रमुख थे।

प्रांतीय अध्यक्ष साथी अपर्णा सेनगुप्ता के नेतृत्व में धनबाद उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी जिसमें साथी मोफिज साहित, साथी शानु चौधरी, साथी हंजला बिन हक, साथी सलाउद्दीन, साथी विशेवश्वर प्रसाद, साथी फातिमा खातून आदि नेताओं ने गिरफ्तारी दी। देवघर के जिलाअध्यक्ष साथी अरविन्द कुमार पाण्डेय, साथी मुरारी लाल बरवाला, साथी जयन्त कुमार, साथी विरेन्द्र पाण्डेय, साथी धीरेन्द्र प्रसाद सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष अपनी गिरफ्तारी दी।

गिरीडीह में साथी सोमनाथ मुखर्जी, साथी संतु गोस्वामी, साथी शास्त्री कुमार वैद्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह मधुपुर रेलमार्ग को जाम कर अपनी गिरफ्तारी दी।

जामताड़ा में साथी अरूण मंडल, साथी लोलिन मुर्मू, साथी भीममंडल के नेतृत्व में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी।

बोकारो में साथी प्रदीप कुमार गोप, चाण्डिल में साथी संतोष महतो, साथी मुणाल कांति महतो, हजारीबाग में साथी रामेश्वर राम कुशवाहा के के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी।

बिहार : चार वामपंथील दलों के राष्ट्रव्यापी जेल भरो अभियान में ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक ने अपने कार्य क्षेत्रों में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पटना में सांसद साथी नरहरि महतो के नेतृत्व में फारवर्ड ब्लॉक के राज्य महासचिव साथी अमेरिका महतो उर्फ आजाद, सचिव वकील ठाकुर, पटना जिला महासवि साथी नारायण सिंह, कोषाध्यक्ष सह राज्य कमिटी सदस्य साथी रवि शंकर साव, अध्यक्ष सह राज्य कमिटी सदस्य साथी बलिराम विश्वकर्मा, पटना जिला सचिव साथी राजेन्द्रनारायण, नथुनी साह, साथी परशुराम प्रसाद ठठरिया, भूपेश गुप्ता उर्फ बम बम, सामेन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष द्वारिका पासवान, युथलीग राज्य महासचिव साथी संदीप कुमार अध्यक्ष साथी दिनेश सिंह, किसा सभा के संयोजक सह आजाद हिन्द स्वयं सेवक के संयोजक साथी प्रभु नारायण सिंह पटना सिटी अनुमंडल कमिटी महासचिव साथी बालमिकी प्रसाद भादुरी, साथी गणेश साव, साथी अशोक कुमार, डॉ पतांजली गोस्वामी, साथी अजय सिंह, अध्यक्ष के साथ हजारों साथियों ने पटना शहर के डाक बंगला चौराहा को तीन घंटे तक जाम रखा और गिरफ्तारी दी।

मुजफ्फरपुर में साथी राम दयाल राम, जिला अध्यक्ष, साथी राकेश कुमार, जिला महासचिव, साथी चन्द्रेश्वर सिंह कार्यालय सचिव, साथी हबीब अंसारी, सचिव, साथी जय नारायण राय, साथी जे.एन. सिंह, उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 300 लोगों ने जिला समाहरणालय के समक्ष गिरफ्तारी दिया।

शिवहर में साथी धीरज कुमार सिंह, साथी वासुदेव राय, साथी चन्देश्वर ठाकुर, साथी प्रेमचन्द राय, साथी उपेन्द्र राय, साथी राम नरेश राय, साथी नागेन्द्र ठाकुर, साथी मेहीलाल साहनी के साथ-साथी साथी धमेन्द्र कुमार अधिवक्ता, महामंत्री यूथलीग दिल्ली प्रदेश राज्य कमिटी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी।

पूर्णियां में साथी नन्द किशोर सिंह, साथी आलोक कुमार कोषाध्यक्ष, साथी रामानन्द साह, सचिव, साथी कामेश्वर सिंह, साथी संतोष कुमार पासवान, साथी ओम प्रकाश दुकानिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर गिरफ्तारी दी।

भोजपुर (आरा) में साथी श्यामसुन्दर पाण्डेय, साथी सुभाष चन्द्र प्रसाद, साथी दिलीप सिंह, सैयद जमीउद्दीन हैदर, सुनील सिंह, विनोद कुमार, विद्यानन्द प्रसाद, साथी राकेश रंजन, राजेन्द्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

नवादा में साथी नरेश चन्द्र विद्यार्थी, साथी राजेश्वर पाण्डेय, साथी तनिक मांझी, साथी सत्येन्द्र सिंह, साथी राजेन्द्र प्रसाद, साथी कैलाश सिंह, साथी लक्ष्मी देवी, साथी मालती देवी, साथी जावेद अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी।

इसके अलावा बक्सर में साथी गोपाल चौबे, साथी मदन मोहन कुमार, साथी राधा कृष्णन कुमार, साथी राम प्रवेश राम, साथी बलिराम मांझी ; कटिहार में साथी नलिनी मंडल, साथी त्रिभुवन पासवान ; कैमुर में साथी ए.सी. प्रजापति, सूर्यकान्त बिन्द उर्फ मोहन बिन्द, साथी राजनारायण राव, साथी सुरेन्द्र प्रसाद बिन्द, ; नालन्दा में साथी गोपाल प्रसाद सिंह, साथी अरूण कुमार मेहता, साथी रामानन्द शर्मा, साथी संजय सिंह, साथी राम प्रवेश राय, साथी बुझो मांझी, साथी सदानन्द सिंह; लखीसराय में साथी राजा प्रसाद, साथी सुरेश महतो, साथी रामकरण पासवान, साथी रघुवर राम, साथी शिवजी साह, साथी शंकर कुमार आदि ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया व गिरफ्तारियां दी।

महाराष्ट्र : राज्यभर में वामदलों के लगभग एक लाख कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा गिरफ्तारी दी। साथी अरूण वांकर, साथी बलवन्त राय मेहता, साथी धर्मराज दुबे सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने नागपुर में गिरफ्तारी दी।

मध्य प्रदेशः लगभग 25000 वाम कार्यकर्ताओं ने 35 जिला केन्द्रों पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। साथी श्याम सुन्दर बिश्नोई, राज्य अध्यक्ष फारवर्ड ब्लॉक ने जिला हरदा में तथा साथी राम अवतार पचौरी ने भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया तथा गिरफ्तारी दी।

कर्नाटक : राज्य में लगभग 15000 लोगों ने प्रदर्शन किया एवं गिरफ्तारी दी। साथी जी.आर. शिवशंकर, टीयूसीसी अध्यक्ष एवं के.सी. वेंकटेश के सहित हजारों फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

उड़ीसा : लगभग 15000 वामकार्यकर्ताओं ने राज्यभर के 30 केन्द्रों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तथा गिरफ्तारी दी। साथी संतोष मित्रा, महासचिव फारवर्ड ब्लॉक राज्य कमिटी ने भूवनेश्वर में तथा बेहराम पुर में साथी मीर सलामत अली ने कार्यक्रम की अगुवाई की।

आसाम : 12 मार्च के दिल्ली चलो रैली में ऐलान के अनुसार 8 अप्रैल 2010 के जेल भरो आन्दोलन में राज्य भर में वामदलों के लगभग 15000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। साथी रत्नेश्वर गोगोई ने आसाम राज्य में फारवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किया।

राजस्थान : लगभग 6500 वाम कैडरों ने राज्यभर में गिरफ्तारी दी। साथी हीराचन्द जैन, राज्य महासचिव फारवर्ड ब्लॉक ने जनता का नेतृत्व किया तथा गिरफ्तारी दी।

पुदूचैरी : लगभग 2200 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा गिरफ्तारी दी। पुदुचैरी में कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठी चार्ज भी किया गया जिसमें लगभग 30 लोग घायल हुये। साथी के. वेंकटेश पुरूमल, राज्य अध्यक्ष फारवर्ड ब्लॉक, साथी यु. मुथु, राज्य महासचिव फारवर्ड ब्लॉक, साथी जी. सुकुमार, कोषाध्यक्ष, आदि ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया तथा गिरफ्तारी दी। साथी जे. मुहम्मदु बिल्लई, राज्य सविच फारवर्ड ब्लॉक के नेतृत्व में कराइकल में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया तथा गिरफ्तारी दी गयी।

लोगों की घोर निराशा ने भारत बंद हड़ताल सफल बनाया

वाम दलों, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक पार्टियों के संयुक्त आह्वान पर 27 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान काफी सफल रहा। महँगाई को रोकने में असफल रही केन्द्र सरकार के लिये यह हड़ताल एक चेतावनी थी।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों बेतहाशा वृद्धि से पीड़ित जनता ने एकजुटता दिखाते हुये इस राष्ट्रव्यापि हड़ताल को सफल बनाने के लिये विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हुये।

सभी क्षेत्रों के कामगारों ने इस हड़ताल में भाग लिया। 13 पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क यातायात, रेल यातायात को कई जगहों पर रोक दिया। कामगार यूनियनों द्वारा घोषणा के बाद कई स्थानों पर हवाई यातायात भी इस हड़ताल से प्रभावित हुई।

पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में हड़ताल पूरी तरह कामयाब रहा। कई राज्यों में लोगों ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन भी किया। वामदलों, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों, और लोकतांत्रिक पार्टियों के कई नेताओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों में गिरफ्तार भी किया गया। झारखण्ड में फारवर्ड ब्लॉक के राज्य महासचिव साथी जनार्दन पाण्डेय को गिरफ्तार कर किया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को वापस न लेने के सरकार के कठोर रवैये के खिलाफ हड़ताल को ऐतिहासि सफलता दिलाने के लिये लोगों को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक बधाई देती है। इस हड़ताल के कारण किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करने के लिये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक अपना खेद व्यक्त करता है।

टीयूसीसी और वीवी गिरी का संयुक्त एजुकेशनल क्लास

भोपालः 15 से 17 अप्रैल 2010 को हिन्दी लैक्चरर हॉल, एनटीटीटीआर, भोपाल में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन टीयूसीसी और वीवी गिरी राष्ट्रीय लेबर संस्थान द्वारा किया गया। जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से कन्सट्रक्शन वर्कर्स एवं बीड़ी वर्कर्स के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। महिलाओं की भागीदारी कार्यक्रम में काफी उत्साहजनक थी।

साथी देवब्रत बिश्वास, महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने 15 अप्रैल 2010 को कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये बताया की कमजोर मजदूर संगठनों के कारण मजदूरों का उनके अधिकारों से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मजदूर नेताओं को उभारने की योजना पर बल दिया।

वीवी गिरी की ओर से डॉ. पूनम चौहान, डॉ. एम.एम. रहमान और टीयूसीसी की ओर से साथी एस.पी. तिवारी, साथी हंसराज अकेला, साथी पी. एन. द्विवेदी, साथी अनिल शर्मा, आदि ने लैक्चर दिया।